



NEERAJ®

M.E.D.-2

सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियां

(Sustainable Development: Issues and Challenges)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Vaishali Gupta, M.Com



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ (Sustainable Development: Issues and Challenges)

Question Paper—June-2024 (Solved)	1-2
Question Paper—December-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—June-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1-3
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	सतत विकास क्या है? (What is Sustainable Development?)	1
2.	सतत विकास के परिमाण (Parameters of Sustainable Development)	9
3.	सतत विकास के अध्ययन के उपागम	14
	(Approaches of Sustainable Development Studies)	
4.	मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Issues and Challenges)	19
5.	प्राकृतिक संसाधनों का दोहन (Exploitation of Natural Resources)	25
6.	औद्योगीकरण के प्रतिरूप (Patterns of Industrialisation)	39
7.	असमान विकास (Unequal Development)	45

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
8.	क्षेत्रीय व भूमंडलीय समस्याएँ (Regional and Global Problems)	53
9.	राज्य द्वारा किए गए प्रयास (Efforts made by State)	60
10.	क्षेत्रीय प्रयास (Regional Efforts)	70
11.	भूमंडलीय प्रयास (Global Efforts)	76
12.	नागरिक समाज तथा सामुदायिक प्रयास (Civic Society and Community Efforts)	85
13.	सामुदायिक ज्ञान (Community Understanding)	90
14.	साज-सज्जा प्रौद्योगिकी (Decoration Technology)	96
15.	नव्य प्रक्रियात्मक व्यवहार (Modern Processing Behaviour)	103
16.	सहयोग और भागीदारी (Cooperation and Participation)	112



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ
(Sustainable Development: Issues and Challenges)

M.E.D.-2

समय : 2 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. (अ) 'सतत् विकास' क्या है? सतत् विकास के उद्देश्यों की उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'सतत् विकास', 'सतत् विकास के उद्देश्य'

(ब) समाज के सतत् विकास पर औद्योगीकरण और शहरीकरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'औद्योगीकरण', पृष्ठ-3, 'शहरीकरण'

प्रश्न 2. (अ) 'ग्रहण क्षमता' को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता किस प्रकार खतरे में है, इसके बारे में उपयुक्त उदाहरणों द्वारा विस्तार से लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-9, 'ग्रहण क्षमता की अवधारणा'

(ब) लैंगिक असमानता को कम करने से सतत् विकास कैसे बढ़ सकता है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'लैंगिक विषमता'

प्रश्न 3. (अ) सतत् विकास के अध्ययन के लिए 'बहुआयामी' उपागम से क्या तात्पर्य है? पर्यावरणीय अच्छे तथा सतत् विकास का अध्ययन करने के लिए किन्हीं पाँच संबद्ध दृष्टिकोण को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-18, प्रश्न 2

(ब) "गरीबी, पर्यावरण तथा सतत् विकास के बीच एक निश्चित संबंध है।" विस्तार से बताइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-16, 'निर्धनता निवारक कार्य नीतियाँ'

प्रश्न 4. (अ) सतत् आर्थिक विकास की चुनौतियाँ क्या हैं? नवोन्मेषी तरीकों से इन चुनौतियों पर किस प्रकार से काबू पाया जा रहा है?

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-21, प्रश्न 1

(ब) "उपयुक्त अथवा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी" की व्याख्या कीजिए। वैकल्पिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार से प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहने में सहायता करता है? उचित उदाहरणों की सहायता से अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-22, प्रश्न 3 तथा पृष्ठ-23, प्रश्न 1

प्रश्न 5. (अ) कृषि में सतत् उपज के तरीकों की व्याख्या कीजिए तथा इनको उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-28, '(i) पौधे की उपज के तरीके'

(ब) भूमंडल तपन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम बताएं।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-57, प्रश्न 4

प्रश्न 6. (अ) भारत में पर्यावरणीय कानून के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-68, प्रश्न 4

(ब) सतत् विकास में सहकारिता की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-16, पृष्ठ-113, 'सहकारिता तथा सतत् विकास'

प्रश्न 7. (अ) जैव प्रौद्योगिकी के सततशील उपयोग क्या हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14 पृष्ठ-100, प्रश्न 2

2 / NEERAJ : सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ (JUNE-2024)

(ब) कारीगर शिल्प और कुटीर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ग्रामीण कुटीर उद्योग किसी क्षेत्र के सतत् विकास में कैसे मदद करते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6 पृष्ठ-41, 'कारीगरी शिल्प तथा कुटीर उद्योग', 'ग्रामीण कुटीर उद्योग'

प्रश्न 8. (अ) सरकारी पहलों के कुछ उदाहरण प्रदान करते हुए सतत् विकास के संदर्भ में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7 पृष्ठ-49, 'एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम'

(ब) पर्यावरण तथा विकास पर प्रमुख सम्मेलनों पर टिप्पणी लिखिए और इनमें से किन्हीं दो सम्मेलनों के बारे में विस्तार से लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11 पृष्ठ-76, 'पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित प्रमुख सम्मेलन'



Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
ISSUES AND CHALLENGES)

सतत विकास क्या है?

(What is Sustainable Development?)



परिचय

सतत विकास की अवधारणा 1960 में विकसित हुई, जब लोग पर्यावरण पर औद्योगीकरण के हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। आधुनिक समय में यह एक बहुचर्चित अवधारणा बन चुकी है। सतत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी की क्षमताओं पर विचार करके विकास की चर्चा की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों की गति धीमी होने या बंद होने के भय ने ही सतत विकास जैसी अवधारणा को जन्म दिया। लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालच एवं दुरुपयोग के परिणामस्वरूप ही इस अवधारणा का विकास हुआ। सतत विकास की कार्यप्रणाली कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करती है। इस अध्याय में सतत विकास का अर्थ व अवधारणा पर चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

सततशीलता, विकास तथा सतत विकास का अर्थ

प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवनदायी अनेक तत्व दिये हैं, जिस कारण प्राचीन काल से यहाँ पर जीवन-पोषण होता आ रहा है तथा भविष्य में भी होता रहेगा। किंतु हमने अपनी महत्वाकांक्षी

गतिविधियों के कारण प्रकृति के साथ छेड़खानी की, जिससे मानव जीवन के समक्ष अनेक समस्याएँ पैदा हो गयी हैं। यदि ये गतिविधियाँ निरंतर चलती रहीं, तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति की आघातों को सहने की क्षमता की भी कुछ सीमाएँ हैं। यदि प्रकृति की प्रारम्भिक अवस्था में बदलाव आने लगता है, तो उसे वापस उसी अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता।

इसी के परिणामस्वरूप मानव के समक्ष यह चुनौती है कि वह किस प्रकार अपनी गतिविधियों को निर्धारित करे, ताकि प्रकृति की ग्रहण क्षमता के भीतर वह अपना जीवन क्रम निरंतर बनाए रखे।

सततशीलता “सततशीलता” शब्द की परिभाषा विभिन्न तरीकों से की गई है

- सततशीलता का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया या स्थिति से है, जो सदैव बनी रहे।
- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाये जिससे पारिस्थितिकी (Ecological) संबंधी कोई असंतुलन पैदा न हो, प्रकृति की ग्राह्यता व उत्पादन क्षमता का अतिशोषण न हो।
- सततशीलता की एक न्यूनतम आवश्यक दशा समस्त प्राकृतिक पूँजी संपदा के भण्डार को वर्तमान स्तर पर या उससे ऊपर बनाए रखना है।

प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Union of Conservation of Nature and

2 / NEERAJ : सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ

Natural Resources-IUCN) के सतत जीवन की कार्यनीति (Strategy of Sustainable Living, 1991) में यह उल्लेख किया गया है कि “सतत उपयोग का अर्थ किसी जीव, पारिस्थितिकी प्रणाली अथवा अन्य नवीकरणीय संसाधन का उनकी नवीकरणीय मात्रा के अनुरूप उपयोग है।” अर्थशास्त्री हेमन डेली ने सततशीलता को बनाए रखने के संदर्भ में कुछ विशेष नियम प्रस्तुत किये हैं; जैसे

1. नवीकरण संसाधनों के उपयोग की दर उनकी पुनर्जनन दर से अधिक न हो।
2. गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर नवीकरणीय विकल्पों के विकास की दर से अधिक न हो।
3. प्रदूषण उत्सर्जन की दर पर्यावरण की खपत क्षमता से अधिक न हो।

विकास विकास का शब्दिक अर्थ सामाजिक व आर्थिक सुधार है। विकास की आवश्यकता विश्व के सभी निवासियों के लिए अवसरों, समृद्धि तथा विकल्पों का निर्माण करने के लिए है, किंतु विकास की ओर इस प्रकार अग्रसर होना चाहिए जिससे भावी पीढ़ियों के समक्ष भी चयन की सुविधा बनी रहे।

सतत विकास सतत विकास में दो शब्द निहित हैं ‘सतत’ तथा ‘विकास’, जिसका अर्थ है विकास या अभिवृद्धि इस प्रकार हो जिसमें प्रकृति के समग्र संसाधनों का प्रयोग उसे बिना नुकसान पहुँचाये करते हुए अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। सतत विकास की सर्वाधिक व्यापक परिभाषा ब्रुटलैण्ड आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ 1987 में दी है। उसके अनुसार सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किये वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करता है।

सतत विकास मनुष्य तथा पर्यावरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चेतवनी देता है कि विकास की ओर अग्रसर होते हुए मनुष्य प्रकृति की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में विजय प्रकृति की ही होगी। सतत विकास उत्पादन व उपभोग के लिए इस प्रकार की तकनीक प्रस्तुत करता है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना समाज व अर्थव्यवस्था को प्रगति की ओर ले जाना है। सतत विकास की सफलता के लिए आवश्यक है कि वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकार के दृष्टिकोण में सुधार हो।

सतत विकास के उद्देश्य सतत विकास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. दुरुपयोग तथा व्यर्थ उपभोग से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण व संरक्षण हो।
2. इस प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकों की खोज की जाए, जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो।
3. अधिकांश लोगों का जीवन-स्तर क्षमता तथा न्याय के साथ हो।
4. विविधता का सम्मान करना तथा स्थानीय तथा देशी समुदायों को और अधिक बुनियादी रुझान वाली तथा प्रासंगिक विकास नीतियों के लिए शामिल करना।
5. ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो गरीब देशों की आवश्यकताओं को मान्यता दे तथा उनकी प्राकृतिक संपदा व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये बिना अभिवृद्धि लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करे।
6. शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण करना तथा उन्हें अधिक लोचशील, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना।
7. विश्व के सभी राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना, क्योंकि शान्ति ही ऐसा माध्यम है, जो उन्हें मानवता के व्यापक हितों में नवीनता लाने में सहायता देगी।

(सकल राष्ट्रीय उत्पाद के) अभिवृद्धि प्रतिमान के आलोचक परम्परागत तौर पर किसी राष्ट्र की अभिवृद्धि को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product—GDP) तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product—GNP) का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों से उत्पादन की मात्रात्मक अभिवृद्धि का पता चलता है, किंतु किसी राष्ट्र की संस्कृति व मानवीय मूल्यों के विकास को इससे नहीं मापा जा सकता। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन का मुख्य केन्द्र मूर्त उत्पाद ही होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, पशुओं, पेड़ों की जैव विविधता और जमीन के नीचे पानी के स्तर को बनाए रखने आदि जैसे अमूर्त मूल्यों का आकलन करना इससे संभव नहीं है। सकल आय अभिवृद्धि का संकेत यह नहीं है कि इससे गरीबी में कमी आती है। अभिवृद्धि प्रतिमान ने विश्व में आय वितरण पर अपना ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप अमीरी व गरीबी के मध्य की खाई गहरी होती गई।

औद्योगिकरण अठारहवीं शताब्दी के मध्य के उपरांत इंग्लैंड में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने एक नई उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया, वह थी कारखाना प्रणाली।

जल्दी ही यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगीकरण आरंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन में परिवर्तन तक सीमित नहीं था, इसके सामाजिक कारणों व गंभीर सामाजिक प्रभावों के कारण यह एक सामाजिक क्रांति बन गई थी। औद्योगिक क्रांति एक तरफ काफी संपन्नता लाई, किंतु दूसरी तरफ यह काफी दुर्दशा के लिए भी जिम्मेदार थी। जहाँ औद्योगिक क्रांति ने समाज को दहन इंजन तथा लेजर रेडियल हाथ दिए वहीं समाज तथा पर्यावरण पर अपने खतरनाक प्रभाव भी छोड़े। औद्योगिक क्रांति को संसाधनों के रूप में कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो कि गरीब देशों में उपलब्ध था। संसाधनों की भरपाई दक्षिण के देशों से की गई तथा मूल्य जोड़ केवल उत्तर के देशों अर्थात् विकसित देशों में किया गया, जिसने आर्थिक असंतुलन पैदा किया। 1950 के दशक के बाद उत्तर के देशों में औद्योगीकरण की गति और तेज हुई, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का पर्याप्त उपयोग व विनाश भी हुआ। इस औद्योगिक उत्पादन ने सोवियत संघ तथा उत्तरी यूरोप में न केवल आर्थिक विस्थापन किया, बल्कि इसके दुष्परिणामों के नतीजे के रूप में अरल सागर का सूख जाना, नाभिकीय प्रदूषण तथा वायु तथा जल के उच्च स्तर पर प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। औद्योगीकरण के कारण सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इस वृद्धि के अंतर्गत बिजली उत्पादन तथा परिवहन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि में मशीनी उपकरणों तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी बढ़ा। इससे पर्यावरण की समस्याएँ पैदा हुईं। इन समस्याओं के कारण प्रदूषण स्तर उच्च हुआ तथा कई प्रजातियाँ पृथ्वी से समाप्त होने लगीं। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अमीर तथा गरीब देश औद्योगिक गतिविधियों की खतरनाक तेजी के विरुद्ध अपना रहे हैं।

शहरीकरण औद्योगीकरण का ही एक अन्य प्रभाव है, शहरीकरण। औद्योगीकरण में वृद्धि से ही शहरों का विस्तार हुआ। शहरों तथा औद्योगिक कस्बों के विस्तार से एक तरफ कृषि तथा जंगल संसाधनों की क्षति होती है तथा दूसरी तरफ शहर की भाँति तीव्र व अप्रबंधनीय प्रवासन होता है।

शहरों तथा कस्बों के अनियंत्रित विस्तार से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे मौलिक सुविधाओं पर तो दबाव पड़ा ही, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी बढ़ गईं। गरीबी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। गरीब शहरी निवासियों को हम तीन वर्गों में बाँटते हैं गृहहीन, मलिन (स्लम) बस्तियों में रहने वाले तथा अनधिकृत झुग्गियों में रहने वाले निवासी। ये गरीब शहरी स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति व सफाई व्यवस्था से वंचित रहने

के कारण अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। शहरों में कूड़े तथा औद्योगिक कचरे के ढेर एकत्रित रहते हैं, जिसके कारण वायु तथा जल प्रदूषण जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। शहरीकरण का अन्य प्रभाव यह भी है कि शहर अपने आस-पास के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं तथा प्रदूषण व कचरा पैदा करते हैं। इससे जंगलों का विनाश होता है, नदियाँ भी प्रदूषित होती हैं, जिससे जलप्राणियों के जीवन व निचली मानव बसावटों के समक्ष अन्य गंभीर समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के पास शहरी केन्द्र होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

असमताएँ मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI) द्वारा पता चलता है कि उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच अंतर में काफी वृद्धि हो रही है। एक तरफ विश्व जनसंख्या के अमीर अल्पसंख्यकों के उच्च असतत उपभोग के कारण भूमण्डलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच रहा है, तो दूसरी तरफ विश्व की बढ़ती हुई गरीब जनसंख्या को अपनी गरीबी के कारण अपने उन प्राकृतिक संसाधनों के भंडार को कम करना पड़ रहा है, जिन पर वह प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। विश्व की लगभग 77% जनसंख्या का निवास विकासशील देशों में है, जिन्हें विश्व की कुल आय का केवल 15% भाग प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले दशकों में गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी। इस वृद्धि के लिए काफी हद तक उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही अनुचित विकासात्मक नीतियाँ हैं। इनके कारण हमारे समक्ष कुछ मुद्दे उभरे हैं; जैसे

1. उत्पादन स्थल पर कृषि तथा घरेलू औद्योगिक उत्पादों में मूल्य किस प्रकार जोड़ा जाए;
2. गरीब बच्चों, निराश्रित नारियों तथा दलितों की सेवा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार से कल्याण कोष उपलब्ध कराये जायें; तथा
3. आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में संपत्तिवान तथा संपत्तिविहीन लोगों के बढ़ते हुए अंतर को किस प्रकार कम किया जाये।

संसाधन उपयोग इस पृथ्वी के चार प्रमुख संसाधनों भूमि, जल, वायु तथा वनों पर सभी राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। औद्योगिक देश, जैसे जी-8 (अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा रूस) आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) तथा यूरोपीय संघ जहाँ विश्व जनसंख्या

4 / NEERAJ : सतत विकास : मुद्दे और चुनौतियाँ

का लगभग 23 प्रतिशत निवास करता है, संपूर्ण एशिया, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के द्वारा किये जाने वाले उपभोग की तुलना में कई गुणा ज्यादा संसाधन उपयोग कर रहे हैं। उत्तरी देशों के विकास से क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) जैसी खतरनाक गैसों का पर्यावरण में मिश्रण होता जा रहा है। इसमें 28% का योगदान अकेले अमेरिका का है। दूसरी ओर गरीब देश ऋण के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि ऋण चुकता करने के लिए उन्हें अपने संसाधनों का अति दोहन करना व उन्हें अमीर देशों को बेचना एक मजबूरी बन चुका है।

सतत विकास की अवधारणा का उदय

1960 में वैज्ञानिक रॉकल कारसन (Rachel Carson) की पुस्तक 'दी साइलेंट स्प्रिंग' (The Silent Spring) ने सतत विकास की अवधारणा को जन्म दिया। कीटनाशक डी.डी.टी. (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) के वन्य जीवन पर पड़ रहे दुष्परिणामों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित इसी पुस्तक ने किया। इसके उपरांत जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इहरलिच ने 1968 में 'पापुलेशन बम' (Population Bomb) नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 1969 में गैर-लाभकारी संस्था 'फ्रेंड्स ऑफ दी अर्थ' (Friends of the Earth) का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की पतन से सुरक्षा के लिए निर्णय प्रक्रिया में आम नागरिकों का भी योगदान रहे। औद्योगिक विकास पर्यावरण को तहस-नहस कर रहा है। इस बात से उत्तर के देशों की सरकारें भी सहमत हो गयी थीं। 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास के लिए संगठन (OECD) ने एक सिद्धांत बनाया, जिसका नाम था "प्रदूषक खर्चा दे" (Polluter Pays Principal)। इसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को कीमत चुकानी चाहिए। 1972 में 'लिमिट्स टू ग्रोथ' (Limits to Growth) नामक एक रिपोर्ट ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। यह रिपोर्ट मेसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology) के युवा वैज्ञानिकों के एक समूह 'क्लब ऑफ रोम' (Club of Rome) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

इस रिपोर्ट में उन गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई थी, जो अभिवृद्धि को धीमा न करने से पैदा होने वाले थे। 1972 में, सर्वप्रथम स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCHE) के आयोजन के अंतर्गत पर्यावरण को एक गंभीर समस्या मानकर इस पर विचार किया गया। 1974 में विश्व चर्च परिषद (World Council of Churches) द्वारा बुलाए गए मानव विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

के अध्ययन सम्मेलन में 'सतत समाज' की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। पहले सतत समाज अवधारणा का संबंध पर्यावरण से नहीं, बल्कि न्याय युक्त वितरण से था। 1980 में दो विद्वानों एवा बालफोअर (Eva Balfour) तथा वेक जेकसन (Wek Jackson) ने सतत विकास की अवधारणा सामने रखी। 1992 के पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो सम्मेलन) में इस अवधारणा को व्यापक बनाते हुए इसमें विकास की पूर्ण अवधारणा को सम्मिलित किया गया। इस अवधारणा को अंतर्विषयक अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा मानते हुए इसे पर्यावरण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान तथा लिंग अध्ययनों में शामिल कर लिया गया। 2000 तक सतत विकास की अवधारणा की स्थापना सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निदेशित सिद्धांत के रूप में हो चुकी थी तथा तभी से संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य सतत विकास कार्यक्रमों तथा कार्यनीतियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करते हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission for Sustainable Development-CSD) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

सतत विकास की परिभाषाएँ (आयाम तथा अवधारणाएँ)

विश्व परिरक्षण कार्यनीति रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा 'परिरक्षण तथा विकास के एकीकरण' के रूप में की गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लोगों का जीवन ग्रह में संशोधन से सुरक्षित रहें व उनका कल्याण हो।

ब्रुटलैंड रिपोर्ट, 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। यह आयोग नार्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हारलम की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1987 में 'अवर कॉमन फ्यूचर' (Our Common Future) के नाम से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें सतत विकास की परिभाषा में दो प्रमुख अवधारणाएँ निहित थीं

- (i) आवश्यकता की अवधारणा, विशेषतः संसार के गरीब लोगों की आवश्यकताएँ, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (ii) सीमितता का विचार जिसका आरोपण प्रौद्योगिकी की स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

ब्रुटलैंड रिपोर्ट को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया। क्योंकि यह रिपोर्ट उस समय जारी हुई थी जब सन 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र के विषय में पता चला तथा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना घटी, जिससे पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी तरंगे फैल गईं।